



NCCT CO-OP NEWS BULLETIN



Date: 14.03.2024

Sr No	Date	Publication	Edition/Language	Page no.	Circulation
1.	11-03-2024	Viksit Bharat Samachar	Guwahati	2	48900
2.	12-03-2024	Sentinel	Guwahati	9	55000
3.	12-03-2024	Jagruk Express	Varanasi	2	37000
4.	12-03-2024	Allahabad Express	Prayagraj	7	44000
5.	13-03-2024	Dainik Bhaskar	Lucknow	11	64000
6.	14-03-2024	Prabhatha Udayam	Andhra Pradesh/ Telugu	1	12000

Publication:	VIKSIT BHARAT SAMACHAR, Pg 2	Edition: Guwahati	Print
Published Date:	March 11, 2024		

कनकलता महिला शहरी सहकारी बैंक महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित

कोऑपरेटिव बैंक महिलाओं के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करके उनके सशक्तिकरण पर बल देता है। इसमें जोखिम कवर के आश्वासन के साथ–साथ उनकी जरूरतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इसने सभी महिला कार्यबल और सदस्य बल की क्षमता का उपयोग करके एक पथ प्रशस्त किया है, जब सहकारी समितियों की भावना महिला सशक्तीकरण के दृष्टिकोण को पूरा करती है तो क्या हासिल किया जा सकता है। विस्तार के प्रति बैंक की स्पष्ट दृष्टि और प्रतिबद्धता इसकी निरंतर सफलता सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के सदस्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संभावित रूप से प्रदान किया जाने वाला नियमित प्रशिक्षण, बैंक के प्रशासन और ज्ञान के आधार को मजबूत करता है। बैंक की शुरुआत 52 व्यक्तियों द्वारा की गई थी।

जोरहाट। कनकलता महिला शहरी सहकारी बैंक, जोरहाट इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे सहकारी आंदोलन ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। महिला दिवस पर यह एक प्रेरणा स्रोत है। 1998 में स्थापित और स्वतंत्रता सेनानी शहीद कनकलता बरुआ के नाम पर, यह असम में एकमात्र महिला बैंक है। इसके 25,000 से अधिक खाते हैं, और 300 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को इसकी क्रेडिट योजनाओं से लाभ हुआ है। यह अनूठी संस्था न केवल महिला दिवस पर, बल्कि संपूर्ण सहकारी आंदोलन के प्रेरणास्पद है। सदस्यों की उधार लेने की क्षमता न्यूनतम श्रेणी में 1,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। बैंक प्रतिदिन 250 से अधिक प्राहकों को सेवा प्रदान करता है। कनकलता महिला अर्बन

Publication:	Sentinel, Pg 9	Edition: Guwahati	Print
Published Date:	March 12, 2024		

The news is about the Konoklota Mahila Urban co-op Bank which is ensuring women's economic independence and participation in the financial sector

कनकलता महिला शहरी सहकारी बैंक महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन को दे रही है बढ़ावा

जोरहाट, 11 मार्च (एसं)। कनकलता महिला शहरी सहकारी बैंक, जोरहाट इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे सहकारी आंदोलन ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। महिला दिवस पर यह एक प्रेरणा स्रोत है। 1998 में स्थापित और स्वतंत्रता सेनानी शहीदकनकलता बरुआ के नाम पर, यह असम में एकमात्र महिला बैंक है। इसके 25,000 से अधिक खाते हैं, और 300 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को इसकी क्रेडिट योजनाओं से लाभ हुआ है। यह अनूठी संस्था न केवल महिला दिवस पर, बल्कि संपूर्ण सहकारी आंदोलन के प्रेरणास्पद है। सदस्यों की उधार लेने की क्षमता न्यूनतम श्रेणी में 1,000 रुपये से बढाकर-50,000 रुपये कर दी गई है। बैंक प्रतिदिन 250 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महिलाओं के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करके उनके सशक्तिकरण पर बलदेता है। इसमें जोखिम कवर के आश्वासन के साथ-साथ उनकी जरूरतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इसने सभी महिला कार्यबल और सदस्य बल की क्षमता का उपयोग करके एक पथ प्रशस्त किया है, जब सहकारी समितियों की भावना महिला सशक्तीकरण के दृष्टिकोण को पूरा करती है तो क्या हासिल किया जा सकता है। विस्तार के प्रति बैंक की स्पष्ट दुष्टि और प्रतिबद्धता इसकी निरंतर सफलता सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के सदस्यों के लिए भारतीय रिजुर्व बैंक द्वारा संभावित रूप से प्रदान किया जाने वाला नियमित प्रशिक्षण, बैंक के प्रशासन और ज्ञान के आधार को मजबूत करता है। बैंक की शुरुआत 52 व्यक्तियों द्वारा की गई थी। मुख्य आरंभकर्ता पद्मश्री श्रीमती लखिमी बरुआर्थी। इसकी शाखाएं राज्य के तीन जिलों में हैं। जोरहाट, गोलाघाट और शिवसागर जिलों में सेवारत, इसके 70 प्रतिशत से अधिक ग्राहक निरक्षर हैं।

Publication:	Jagruk Express, pg 2	Edition: Varanasi	Print
Published Date:	March 12, 2024		

डेटाबेस से सहकारिता क्षेत्र का विस्तार, डेवलपमेंट और डिलीवरी सुनिश्चित होगी : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह

छोडी। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कशल मार्गदर्शन में जर्जर हो चुकी सहकारी समितियाँ जीवंत हो चुकी हैं। देश भर के पैक्स सेंट्रलाइज्ड और कंप्युटराइज्ड हो गए हैं। अब देश भर में पैक्स को बहुउद्देश्यीय बनाया जा रहा है। अंत्योदय की राजनीति करने वाले अमित शाह का बार-बार यह कहना भी सच साबित होने वाला है कि साल 2027 तक देश के हर पंचायत में एक पैक्स होगा। यही वजह है कि राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण किया गया है जो देशभर में कहाँ सहकारी समितियां कम है, उस गैप की पहचान कर सहकारिता के विस्तार में मददगार साबित होगा।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन करने का काम पूरा किया और इसकी कमान केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह को सौंप दी। अपने शुरूआती दिनों से ही सहकारिता क्षेत्र से जुड़े रहने वाले शाह ने कुछ ही वर्षों में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने में कोई कोर-कसर नहीं

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय डेटाबेस का लोकार्पण किया। सहकारिता आंदोलन से जुड़े शाह यह मानते हैं कि, ह्यडेटाबेस से सहकारिता क्षेत्र का विस्तार, डेवलपमेंट और डिलीवरी सुनिश्चित होगी।'

आजादी के बाद दशकों तक अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन की मांग होती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन सहकारिता क्षेत्र की स्थिति बद-से-बदतर होती चली गई। साल 2021 में दूरदर्शी



Publication:	Allahabad Express, pg 7	Edition: Prayagraj	Print
Published Date:	March 12, 2024		

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस : एक क्लिक से प्राप्त करें सहकारी क्षेत्र की सारी जानकारी

इलाहाबाद एक्सप्रेस

प्रयागराज। केंद्र सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया है, जिससे कंप्यूटर पर माउस के एक

क्लिक से विशाल सहकारी क्षेत्र से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना संभव हो गया है।

सहकारी डेटाबेस नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करेगा।

शुक्रवार को, राष्ट्रीय राजधानी में डेटाबेस लॉन्च करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय डेटाबेस एक कम्पास

की तरह सहकारी क्षेत्र के विकास को दिशा देगा। सहकारिता डेटाबेस पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और स्टेकहोल्डर्स के लिए अमूल्य संसाधन का काम करेगा।

शाह ने कहा कि डेटाबेस में पैक्स से एपैक्स, गांव से शहर, मंडी से ग्लोबल मार्केट और स्टेट से अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तक जोड़ने की पूरी संभावना मौजूद है। शाह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ा है जिससे पैक्स मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से इनके विकास की कई संभावनाएं खुलीं और ये तय किया गया कि 2027 से पहले देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा। राष्ट्रीय डेटाबेस उन गैप्स की पहचान करेगा जहां हमारे पास कम संख्या में सहकारी समितियां हैं, जिससे कि सहकारी क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी । इस डेटाबेस के आंकड़ों की प्रामाणिकता और उन्हें अपडेट करने के लिए पूरी साइंटिफिक व्यवस्था की गई है।

> उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि इस डेटाबेस पर सत्यापित डाटा ही नियमित रूप से अपलोड हो।

उन्होंने बताया कि 1975 के बाद देश में सहकारिता आंदोलन की गति बहुत कम होती गई क्योंकि हमारे यहां भौगोलिक असंतुलित विकास हुआ। इसके साथ ही, क्षेत्रीय असंतुलन, सामुदायिक असंतुलन और कार्यात्मक असंतुलन भी बढ़ा है।

हालाँकि, इन चारों समस्याओं का समाधान टूल्स के साथ इस डेटाबेस में डाला गया है। उन्होंने कहा कि हज़ारों लोगों, संघों और राज्यों ने मिलकर एक भागीरथ काम को अंजाम दिया है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि 60 के दशक के बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्य के सहकारिता आंदोलन के बीच समन्वय हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने साहसिक फैसला लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हुए केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।

उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋग समितियों कम्प्यूटराइज़्ड हो गए हैं, उनके कारोबार में वृद्धि करने के लिए कॉमन बायलॉज़ सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है।



Publication:	Dainik Bhaskar, pg 11	Edition: Lucknow	Print
Published Date:	March 13, 2024		

बस एक क्लिक से सहकारी क्षेत्र की सारी जानकारी प्राप्त करें

लखनऊ। केंद्र सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया है, जिससे कंप्यूटर पर माउस के एक क्लिक से विशाल सहकारी क्षेत्र से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना संभव हो गया है।



सहकारी डेटाबेस नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय राजधानी में डेटाबेस लॉन्च करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय डेटाबेस एक कम्पास की तरह सहकारी क्षेंत्र के विकास को दिशा देगा। सहकारिता डेटाबेस पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और स्टेकहोल्डर्स के लिए अमूल्य संसाधन का काम करेगा। शाह ने कहा कि डेटाबेस में पैक्स से एपैक्स, गांव से शहर, मंडी से ग्लोबल मार्केट और स्टेट से अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तक जोड़ने की पूरी संभावना मौजूद है। शाह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ा है जिससे पैक्स मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से इनके विकास की कई संभावनाएं खुलीं और ये तय किया गया कि 2027 से पहले देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा। राष्ट्रीय डेटाबेस उन गैप्स की पहचान करेगा जहां हमारे पास कम संख्या में सहकारी समितियां हैं, जिससे कि सहकारी क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी।

Publication:	Prabhatha Udayam; pg 1	Edition: Andhra Pradesh	Print
Published Date:	March 14, 2024		

The news pertains to the inauguration of the new buildings for the cooperative sector



LOCATIONS OF NCCT INSTITUTES

